भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4568

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति

4568. डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे परिवारों की कुल संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के अंतर्गत अब तक पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और शहरी गरीबों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत विभिन्न शहरों में अवसंरचना और डिजिटल सेवाओं में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास, शहरी सेवाओं, स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) विभिन्न मिशनों, जैसे कि प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.73 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और दिनांक 17.03.2025 तक देश भर में 91.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.09.2024 से अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है।

एससीएम शहरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके बढ़ावा देता है और 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण ने अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं से तालमेल, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि जैसे कई वितपोषण स्रोतों से निवेश को बढ़ावा दिया। मिशन में 100 शहरों ने 1,64,545 करोड़ रुपए की कुल 8,063 परियोजनाएँ शुरू की हैं। 100 स्मार्ट सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, दिनांक 04.03.2025 तक 1,50,306 करोड़ रुपए की 7,504 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

एसबीएम-यू को 2 अक्टूबर 2014 से शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने और वहां उत्पन्न होने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एसबीएम-यू के तहत कुल 10,617.31 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम-यू 2.0 की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाना, उनमें सभी पुराने कचरा डंपसाइटों का सुधार और इस्तेमाल किए गए पानी का शोधन करना है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, अब तक तीन घटकों आईएचएचएल/यूडब्ल्यूएम/एसडब्ल्यूएम (मिशन अवधि 2021-2026 के लिए 28,033.89 करोड़ रुपए के मिशन आवंटन में से) के लिए क्रमशः 5,420.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अमृत योजना को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकसित योजनाओं के आधार पर 1 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले 500 चयनित शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा, शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें 76,760 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता सहित 2,77,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश शामिल है।

*****